Inclusion of more items in PDS list

689. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA : Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state :

(a) whether Government have recently decided to include and supply more items in the PDS list;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether the expert committee appointed by Government to look into the reasons for poor performance of the cooperatives and to suggest ways to revitalise them has submitted its report to Government ;

(d) if so, the findings of the report; and

(e) the steps Government propose to take thereon ?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI A. K. ANTONY): (a) and (b) No Sir. The Central Government is responsible for procurement, transportation, storage and supply of bulk quantities of six essential commodities namely, Rice, Wheat, Sugar, Soft Coke, Superior Kerosene Oil and imported edible oil. The State Governments and U.T. Administrations are free to add, on their own, other items of mass consumption based on the local needs and preferences.

(c) No, Sir.

(d) and (e) Do not arise.

Public Utilities Regulatory Commission

690. SHRI G. Y. KRISHNAN: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state :

(a) whether the proposed Public Utilities Regulatory Commission (PURC), envisaged as a watchdog body to protect the interests of the consumer has been set up by the Ministries dealing with public utilities like Railways, Communications etc.;

(b) if not, the reasons therefor; and

(c) how Government propose to tackle the situation and ensure early constitution of the utilities watchdog commission and enunciate its functions ?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI A. K. ANTONY): (a) to (c) The matter regarding setting up of Public Utilities Regulatory Commission is under the consideration of the Government.

मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवकों को उचित दर की दुकानों का आवंटन

691. **श्री अजीत जोगी :** क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवकों को निकट भविष्य में सहकारी आधार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उचित दर की दुकान आवंटित करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रस्तावित योजना को कब से लागू किया जाएगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री ए०के० एंटनी) : (क) से (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु प्रचालन संबंध जिम्मेवारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है । उचित दर दुकानों के आबंटन के लिए पात्रता संबंधी मानदंड, अत: क्षेत्रीय आबंटन, राशन कार्ड जारी करने, उपलब्धता की आवधिकता इत्यादि के संबंध में निर्णय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा लिए जाते हैं। तथापि, केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की सलाह दी है कि वे उचित दर दुकानों का कुछ प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों और महिलाओं को आबंटन करने के लिए सुरक्षित रखें । केन्द्रीय-सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिसमें मध्य प्रदेश शामिल है, के बेरोजगार युवकों क लिए निर्धारित की गई और उन्हें आबंटित की गई उचित दर दुकानों के बारे में आंकड़े नहीं रखते ।

सुपर बाजार में खरीदारियों में अनियमितताएं

692 **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी** : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित सुपर बाजार में करोड़ों रुपए मूल्य के सामान/वस्तुओं की खरीद में अनियमितताओं की रिपोर्ट मिली है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सुपर बाजार की वस्तुओं की खरीद से संबंधित अनेक दस्तावेज गायब हैं ;

(घ) क्या सुपर बाजार की खरीद शाखा में कार्यरत सहायक प्रबंधकों, सहायक कार्मिक प्रबंधक और उपमहाप्रबंधक की मिलीभगत से करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार के मामले हुये हैं ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(च) इसमें शामिल दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ; और

(छ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं, या किये जाने के प्रस्ताव हैं ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री ए०के० एंटनी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य चुनाव अधिकारी ने दिल्ली विधान सभा चुनावों के लिए अपेक्षित लोहे के ट्रंकों की आपूर्ति में सुपर बाजार द्वारा अनियमितताएं बरते जाने की सूचना दी है । मामले को सुपर बाजार के मुख्य सतर्कता अधिकारी की जांच करने के लिए भेजा गया है, जो इस मामले की जांच कर रहे हैं । इस मामले के संबंध में कागजात के गायब होने की कोई सूचना नहीं मिली है ।

(घ) सरकार को सुपर बाजार में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के बारे में कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है ।

(ङ) से (छ) प्रश्न नहीं उठता ।

Rise in prices of wheat and rice in open market

693. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state :

(a) whether the prices of wheat and rice etc. in open market have risen on the expected increase in the prices of specified food items sold through Public Distribution System ;

(b) if so, by how much amount have the prices of wheat, rice etc., gone up in the open market in the ast one year